डीईआईसी के नाम पर स्कूली बच्चों के साथ किया जा रहा है मजाक

फरीदाबाद (म.मो.) बच्चों को स्कूल में ही इलाज की सुविधा देने के नाम पर सरकार द्वारा खोला गया डीईआईसी सेन्टर (डिस्ट्रिक अर्ली इंटरवेंशन सेन्टर) सफेद हाथी साबित हो रहा है। स्कूलों में जांच के बाद खानापूर्ति के लिए जिन बच्चों को यहां इलाज के लिए भेजा जाता है, उन्हें इधर उधर धक्के खाने के सिवा कुछ नहीं मिलता।

ऐसा नहीं है कि इसके लिए सेन्टर में तैनात डाक्टर या अन्य कर्मचारी जिम्मेदार हैं। सही तो यह है कि सरकार ने सेन्टर सिर्फ दिखावे के लिए खोला हुआ है।

सेन्टर को खुले करीब चार साल का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक संसाधन तक जुटाने की जरूरत महसूस नहीं की। कुछ डाक्टर व तकनीशियन खुद नौकरी छोड़ कर चले गए। जबकि कुछ पद सरकार ने खत्म कर कर्मियों को निकाल दिया है। ऐसे में बच्चों को सेन्टर द्वारा किस तरह का इलाज दिया जा रहा है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के तहत दिसबंर 2013 में स्कूली बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से सरकार ने बादशाह खान अस्पताल के कमरा नबंर 23 में डीईआईसी सेन्टर शुरू किया था। सेन्टर में बच्चों के आम रोगों का इलाज करने के साथ साथ जन्मजात बीमारियों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी थी। ऑपरेशन करवाने के लिए बच्चों को अन्य अस्पताल में भेजने की व्यवस्था भी सेन्टर के द्वारा करवाई जानी थी।

सेन्टर में एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक दंत रोग विशेषज्ञ, दो फार्मासिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक ऑडियोलॉजिस्ट, एक लैब तकनीशियन, एक सोशल वर्कर और दो काउंसलरों को तैनात किया गया था। सेन्टर को शुरू हुए कुछ ही समय गुजरा था कि दंत चिकित्सक, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियन का पद सरकार ने सेन्टर से खत्म कर दिया। ऑडियोलॉजिस्ट और एक काउंसलर काम छोड़ कर जा चुके हैं। इन पदों को दोबारा भरने की सरकार ने आज तक जरूरत महसूस नहीं।

सेन्टर में फिजियोथेरेपिस्ट तो तैनात है, लेकिन आज तक यहां फिजियोथेरेपी करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। यहां तैनात महिला फिजियोथेरेपिस्ट कई कई महीने अपनी शक्ल दिखाने के लिए सेन्टर में नहीं आती, हां अधिकारियों की मिलीभगत से हर महीने 30 हजार रुपये वेतन जरूर उसके पास पहुंच जाता है। योजना के तहत स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच करने के लिए दस टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में दो बीएमएस डॉक्टर (एक पुरुष, एक महिला) एक एएनएम और एक फार्मासिस्ट को शामिल किया गया। यह टीमें जांच के बाद मामूली रूप से बीमार पाए जाने वाले बच्चों का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से करवा देती हैं। गंभीर हालत या जन्मजात बीमारी पाए जाने पर इलाज के लिए सेन्टर में भेजा जाता है।

इनमें से छह टीमें बीके अस्पताल, दो तिगांव, एक पाली और एक पल्ला स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तैनात हैं। इन टीमों ने शुरू में तो पूरे जोश के साथ काम किया। जिसके कारण काफी संख्या में बच्चों को इलाज के लिए सेन्टर में भेजा जा रहा था। लेकिन धीरे यहां सिर्फ दिखावा ही किया जाने लगा। कहने को सेन्टर के अंर्तगत छह टीमें तैनात हैं, लेकिन इन टीमों में तैनात सदस्यों को आज तक यहां आते हुए किसी ने नहीं देखा।

टीम में तैनात डाक्टर और कर्मचारी कहां और किसी स्कूल में जांच करने के लिए गए हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। ये लोग सुबह जिला सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा के कार्यालय में हाजरी लगाने के बाद कहां जाते हैं, इसका पता नहीं चलता। काम के नाम पर सेन्टर के कर्मचारी फर्जी आंकड़ेबाजी कर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जिला सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा ने भी कभी फील्ड में जाकर यह जांच करने की जरूरत महसूस नहीं की कि टीमें वास्तव में काम कर भी रही है या नहीं?

दावे मेडिकल कॉलेज खोलने के, इंतजाम रेबिज का भी नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे करने वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार आवारा पशुओं का शिकार बनने के बाद, बादशाह खान अस्पताल में आने वाले लोगों को रेबिज के इंजेक्शन तक उपलब्ध करवाने में नाकाम साबित हो रही है। अब्बल तो अस्पताल की ओपीडी में रेबिज के इंजेक्शन आमतौर पर उपलब्ध होते ही नहीं हैं। लेकिन जब क ी इंजेक्शन आते भी हैं तो कर्मचारी एक दिन में मात्र दर्जनभर लोगों को टीका लगाने के बाद अन्य लोगों को स्टॉक खत्म होने की बात कह कर लौटा देते हैं।

कई बार तो कर्मचारी इंजेक्शन लगाने के बदले में सरेआम रुपये मांगने से भी नहीं चूकते हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों ने जब कुछ महिलाओं से टीका लगाने के बदले में 500 रुपये की मांग कर डाली, उस समय पीड़ितों ने हंगामा तक किया था। सबकुछ पता चलने के बाद भी सिविल सर्जन और पीएमओं ने आज तक भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत महसूस नहीं की।

यूं तो जिला प्रशासन फरीदाबाद को आवारा पशु मुक्त घोषित कर चुका है। लेकिन यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। हकीकत में आज भी नगर निगम की लापरवाही से शहर में आवारा पशुओं का आतंक छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम के पास आवारा पशुओं को पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। निगम ने बकायदा एक दस्ता बना कर उसमें अनेकों कर्मचारियों को तैनात किया हुआ हैं। लेकिन दस्ते के कर्मचारी खानापूर्ति के लिए ही अपनी ड्यूटी बजाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन लोग इन आवारा पशुओं का शिकार बन रहे हैं।

आवारा पशु के काटे जाने के बाद मरीज को चार रेबिज के इंजेक्शन लगवाने होते हैं। बाजार में रेबिज का एक इंजेक्शन 350 रुपये में मिलता है। संपन्न व्यक्ति तो निजी क्लीनिकों में जाकर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। लेकिन गरीब तबके के लोगों को इंजेक्शन लगवाने के लिए बीके अस्पताल के धक्के खाने ही पड़ते हैं।

ऐसा नहीं है कि बीके अस्पताल में रेबिज का इंजेक्शन मुफ्त में लगाया जाता है। एक इंजेक्शन लगवाने के बदले में 100 रुपये शुल्क देना पड़ता है। लेकिन बीके अस्पताल में आमतौर पर इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं होते। अस्पताल में हर रोज करीब 100 से ज्यादा लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं। लेकिन कर्मचारी एक दिन में मात्र दर्जनभर लोगों को इंजेक्शन लगाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं।

स्टॉक आने के बावजूद ओपीडी के कमरा नबंर एक पर तैनात कर्मचारी 'यादातर मरीजों को इंजेक्शन खत्म होने की बात कह कर लौटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बारे में जिला सिविल सर्जन डॉ. गुलशन अरोड़ा को पता नहीं है। पिछले दिनों एक कर्मचारी ने एक महिला से इंजेक्शन लगवाने के बदले में 500 रुपये की मांग कर डाली थी। जिसके बाद वहां मौजूद अन्य लोगों में भी रोष उत्पन्न हो गया। कई महिलाएं इकट्ठी होकर मामले की शिकायत लेकर सिविल सर्जन डॉ. अरोड़ा के पास पहुंची, लेकिन अरोड़ा ने महिलाओं की सुनने की बजाए चपरासी से कहलवा दिया कि वे शिकायत पीएमओ से करें। बाद में इधर उधर धक्के खाने के बाद पीड़ित महिलाएं मजबूर होकर घर लौट गई। अस्पताल में वैसे तो इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक आता ही नहीं है और जब कभी आता है तो उस पर सबसे पहले कर्मचारी ही हाथ साफ कर लेते है। जानकार सूत्र बताते हैं कि स्टॉक के आते ही कर्मचारी इंजेक्शन लगाने का फर्जी रिकॉर्ड बनाने के बाद उसे बाजार में बेच डालते हैं।

ऐसा नहीं है कि कर्मचारी अपने स्तर पर यह घोटाला करते है। कर्मचारी अस्पताल के सीएमओ की मिलीभगत से यह सब करते है। यदि वास्तव में यह सच नहीं है तो आज तक इंजेक्शनों की चोरी करने वाले कर्मचारियों की लगाम कसने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए?

ईएसआई डिस्पेंसरी के मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ता है

फ़रीदाबाद (म.मो.) ईएसआई कारपोरेशन द्वारा एनएच दो स्थित डिस्पेंसरी में आने वाले करीब 15 हजार कार्ड धारकों और उनके परिवारों के साथ इलाज के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। डिस्पेंसरी में पिछले लंबे समय से लैब तकनीशियन का पद खाली पड़ा हुआ है। जिसके कारण डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों को डाक्टर द्वारा अंदाजे से दवाइयां दी जा रही है। मजबूरी में जिन मरीजों को जांच करवाने के लिए लिखा जाता है। उन्हें इधर उधर भटकने को मजबूर होना पड़ता है।

प्रदेश की जनविरोध मनोहर लाल सरकार की मनमानी के चलते ईएसआई की डिस्पेंसरियां कोढ़ में खाज साबित हो रही है। इन डिस्पेंसरियों में डाक्टरों और कर्मचारियों का अभाव तो है ही साथ विभिन्न तरह की सुविधाएं भी नहीं है। डिस्पेंसरियों में जो डाक्टर और कर्मचारी मौजूद है, वे भी काम करने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही हाल एनएच दो में स्थित ईएसआई डिस्पेंसरी का है। डिस्पेंसरी पर करीब 15 हजार परिवारों का इलाज करने की जिम्मेदारी डिस्पेंसरी पर है। इस डिस्पेंसरी में 'यादातर मरीज डबुआ कॉलोनी, गाजीपुर, नवादा, नेहरू कालोनी, एनएच दो और आसपास की कालोनियों से आते है। डिस्पेंसरी में प्रभारी समेत छह डॉक्टरों के पद है लेकिन फिलहाल सिर्फ पांच डॉक्टर तैनात है। डिस्पेंसरी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक भी मौजूद नहीं है।

इसके अलावा यहां छह फर्मासिस्ट, दो क्लर्क और एक सफाई कर्मचारी तैनात है। डिस्पेंसरी का भवन तो खस्ता हालत में है ही साथ ही यहां सफाई व्यवस्था भी बुरी तरह चरमराई हुई है। डिस्पेंसरी परिसर की हालत को देख कर स्पष्ट नजर आता है कि यहां नियमित रूप से साफ-सफाई नहीं होती। डिस्पेंसरी के कमरों में कंडम सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता हैं।

ईएसआई कॉरपोरेशन को हर महीने करोड़ों रुपये देने वाले मरीजों के लिए यहां बैठने तक का इंतजाम नहीं है। मरीजों को अपनी बारी के इंतजार में डाक्टर के कमरे के बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। डॉक्टर से जांच करवाने के बाद इन मरीजों को दोबारा दवा लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती हैं।

डिस्पेंसरी में हर रोज करीब 600 से 700 मरीज इलाज करवाने व दवा लेने के लिए आते है। ऐसा नहीं है कि ईएसआई के पास बजट की कोई कमी है। लेकिन ईएसआई के अधिकारी मज़दूरों को सुविधाएं देने की बजाए उनके खून पसीने की कमाई को अपने आराम के लिए संसाधन जुटाने में खर्च करते हैं।

कहने को डिस्पेंसरी में प्रभारी डॉ. सुमन पंवार समेत पांच डॉक्टर तैनात है। दो शिफ्ट में चलने वाली डिस्पेंसरी में पहली शिफ्ट में तीन डॉक्टर व तीन फार्मासिस्ट और दूसरी में दो डॉक्टर व तीन फार्मासिस्ट मौजूद रहने चाहिए। लेकिन यहां दोनों शिफ्टों के दौरान सिर्फ काम चलाने के लिए डॉक्टर व अन्य कर्मचारी मौजूद रहते है। शुक्रवार 24 नवंबर को सुबह करीब साढ़े नौ बजे जब मज़दूर मोर्चा ने डिस्पेंसरी का दौरा किया तो वहां सिर्फ एक डॉक्टर, दो फार्मासिस्ट, एक क्लर्क और एक सफाई कर्मचारी मौजूद थी। बाकी अन्य डॉक्टर और कर्मचारी नदारद थे। 27 नवंबर सोमवार को शाम की शिफ्ट में करीब साढ़े छह बजे एक डाक्टर, एक क्लर्क और एक फ़ार्मासिस्ट मौजूद था। इसी तरह 28 नवंबर की सुबह करीब पौन आठ बजे डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर, दो फार्मासिस्ट, एक क्लर्क और सफाई कर्मचारी मौजूद थे। इससे स्पष्ट है कि डिस्पेंसरी का काम बारी बारी एक एक डाक्टर, दो दो फ़ार्मासिस्ट और एक एक क्लर्क चलाते है। इस दौरान नदारद रहने वाले डॉक्टर और अन्य कर्मचारी अपने निजी कामों में व्यस्त रहते है। 24 नवंबर को सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर ने अपना नाम बताने से इनकार करते हुए बताया कि प्रभारी डाक्टर छुट्टी पर है। ड्यूटी डॉक्टर का दावा था कि डिस्पेंसरी में किसी तरह की परेशानी नहीं है। दवाईयों का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। डिमांड भेजने पर दवाइयां यहां भेज दी जाती है। लैब तकनीशियन के बारे में डाक्टर ने बताया कि उन्होंने इसकी डिमांड लिखित रूप से भेजी हुई है। फिलहाल जांच के लिए मरीजों को एनएच तीन स्थित ईएसआई अस्पताल में भेज दिया जाता है।

विपुल गोयल भी जुमलेबाज मंत्री हैं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : जुमलेबाज की संतानें तो जुमलेबाज ही निकलती हैं। अगर इस जुमले में कोई शक हो तो आप एनआईटी नं. 2 में ताऊ देवीलाल वृद्ध आश्रम के रिकॉर्ड आकर चेक कर लो। इस आश्रम में भी जुमलेबाज ख़ानदान के लोग पहुंचे और जुमलेबाजी करके चले आए।

हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल का 25 अप्रैल 2017 को जन्मदिन पड़ा तो फ़रीदाबाद में उनके चेलों चपाटो, रिश्तेदारों, संघियों और भाजपाइयों ने इसे बहुत जोरशोर से मनाया। कई कल्याणकारी काम किए गए और इसी के तहत विपुल गोयल के कुछ चेले और रिश्तेदार जा पहुचे ताऊ देवीलाल वृद्ध आश्रम में। आश्रम की परंपरा के मुताबिक़ यहाँ इन लोगों ने खाने की थाली खाई और विपुल गोयल की ओर से एक लाख रूपये आश्रम को देने की घोषणा कर दी। ध्यान रहे कि यह घोषणा विपुल की तरफ़ से की गई न कि हरियाणा सरकार की ओर से।

घोषणा करके और चमचागीरी करने

वाले अख़बारों में फ़ोटो लगवाने के लिए फोटों खिंचवाने के बाद ये लोग वहाँ से चलने लगे तो आश्रम के संचालकों ने बताया कि विपुल गोयल जी के पैसे तो बाद में आ जाएँगे लेकिन आप लोगों ने आश्रम में जो खाने की थाली खाई है उसके 1500 रूपये तो देते जाओ। ख़ैर वो पैसे उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकालकर आश्रम संचालकों को सौंपे।

मज़दूर मोर्चा ने इस घटना पर नज़र रखी और कई महीने बाद जब जानकारी हासिल की कि आश्रम में विपुल गोयल द्वारा घोषित एक लाख की राशि मिली या नहीं। हालाँकि आश्रम के प्रधान किशन लाल बजाज ने हिम्मत नहीं हारी है। बजाज ने कहा कि गोयल जी के लोग एक महीना पहले लेटर लिखवा कर ले गए हैं और हरियाणा सरकार से एक लाख की जगह डेढ़ लाख रूपये की मदद दिलाने का वादा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी वो पैसे आश्रम को ज़रूर दिलाएँगे। विपुल जी बहुत अच्छे आदमी हैं और वह सामाजिक कार्यों और दान आदि में आगे रहते हैं। आश्रम की मदद वो ज़रूर करेंगे।

यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि जब पैसे देने की घोषणा विपुल गोयल के चेलों की ओर से की गई थी तो वह पैसा सरकारी खाते यानी हरियाणा सरकार की ओर से दिलाने की कोशिश क्यों की जा रही है। हरियाणा सरकार का पैसा जनता का पैसा है।

यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार की ओर से नहीं आयोजित किया गया था, यह विपुल गोयल की छवि चमकाने का उनके चेलों द्वारा किया गया असफल प्रयास था। इससे छवि तो चमकी नहीं उल्टा पैसे न देने से जनता में ग़लत संदेश जा रहा है। वरना चेले घोषित करें कि प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह यह भी एक जुमला था जिसका इस्तेमाल आजकल मंत्री कर रहे हैं। हालाँकि हो सकता है कि विपुल गोयल को बिना बताए यह घोषणा उनके चेलों ने अति उत्साह में की हो। अगर यह सच है तो विपुल गोयल को ऐसे चेलों से सतर्क हो जाना चाहिए।